

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809010

पत्र संख्या-चे0पो0-25-क -करापवंचन -08-09/

117

// वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(चेक पोस्ट-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 अप्रैल, 2008

समस्त

एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(वि0 नु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, इटावा

समस्त डिप्टी कमिशनर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ वि0 नु0शा0 /कर निर्धारण)वाणिज्य कर, उ0प्र0।

आप अवगत हैं कि दिनांक 01-01-08 से प्रान्त में मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली लागू की जा चुकी है । मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली लागू होने के उपरान्त प्रवर्तन इकाईयों के कार्यों की समीक्षा पर यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रवर्तन इकाईयों करापवंचको को चिन्हित करने तथा उनके द्वारा करापवंचन हेतु अपनायी गयी मौडैस औपरेन्डी की जानकारी करने तथा प्राथमिकता के आधार पर करापवंचन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रही है । प्रवर्तन इकाईयों का मुख्य दायित्व करापवंचन के मामलों को पकड़ने तथा कर माफियाओं के विरुद्ध डिटेरेन्ट कार्यवाही करना है परन्तु अधिकांश स्तरों पर प्रवर्तन इकाईयों के द्वारा की गयी कार्यवाही समुचित नहीं पायी गयी है । यह भी अनुभव किया गया है कि प्रवर्तन इकाईयों यदा-कदा जब कोई प्रभावी कार्यवाही करती भी हैं तो उससे संबंधित सूचना की शेयरिंग अन्य प्रवर्तन इकाईयों से नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप करापवंचकों द्वारा उस मौडैस औपरेन्डी से कार्य लगातार किया जाता रहता है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रवर्तन इकाई जहाँ अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करें वही ऐसे विशिष्ट मामलों के संबंध में अपने क्षेत्र की तथा अन्य क्षेत्रों की प्रवर्तन इकाईयों से भी सूचना को शेयर करें तथा प्रवर्तन इकाईयों के इस कार्य की समीक्षा साप्ताहिक रूप से ज्वाइन्ट कमिशनर(वि0 नु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर के द्वारा की जाये ।

यह सर्वविदित है कि रेलवे के माध्यम से करापवंचित माल के परिवहन की स्थिति में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्णतः अपर्याप्त है । आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 एवं संबंधित नियमावली में रेलवे से माल का आयात होने की स्थिति में स्पष्ट विशिष्ट व्यवस्था की जा चुकी है परन्तु इन प्राविधानों का प्रभावी उपयोग अभी तक क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाना स्पष्ट नहीं हुआ है । जिन रेलवे स्टेशनों पर एस0एल0 आर0 के माध्यम से माल आ रहा है तथा जिन स्थानों पर रेलवे सिटी बुकिंग एजेन्सियाँ कार्यरत हैं वहाँ इस संबंध में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी जाँच नहीं की गयी है जो अत्यन्त आपत्तिजनक है । सामान्यतः यह समझा जाता है कि रेलवे के माध्यम से करापवंचन रोकने का दायित्व रेलवे जाँच चौकी /रेलवे सचलदल के अधिकारियों का है जबकि पूर्व में ही स्पष्ट आदेश दिये जा चुके हैं कि रेलवे के माध्यम से परिवहित किये जा रहे करापवंचित माल को रोकने का दायित्व प्रवर्तन कार्य में लगे सभी अधिकारियों का है । इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने की तत्काल आवश्यकता है । सभी जोनल एडिशनल कमिशनर एवं ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0 नु0शा0/प्रवर्तन) इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही कराने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / रेलवे अधिकारियों से वार्ता करके प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।

सचलदल इकाइयों का यह दायित्व है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित ट्रान्सपोर्ट कंपनियों के संबंध में विस्तृत जानकारी रखें तथा उनके संबंध में अभिसूचना संकलित कर अपने पास रखे गये रजिस्टर में उनके नाम व पते, वाहन संख्या, वाहन मालिक के नाम व पते आदि दर्ज कराये। करापवंचन में लिप्त ट्रान्सपोर्ट कंपनियों / वाहनों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी की जाये तथा ऐसी जानकारी से मुख्यालय को भी अवगत कराया जाये ताकि इस संबंध में अन्य क्षेत्रों की सचलदल इकाइयों को भी अवगत कराया जा सके। प्रत्येक सचलदल इकाई का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में आने वाले, उनके क्षेत्र से जाने वाले माल की नियमित रूप से एवं योजनाबद्ध ढंग से जाँच करते हुये यह जानकारी करें कि कहीं कोई व्यापारी करापवंचन में लिप्त तो नहीं है। ऐसे व्यापारियों के संबंधित बिलों का संग्रहण और उनका तत्काल कर निर्धारण अधिकारियों से मिलान कराया जाना इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिये। अपने द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी को गोपनीय रूप से उच्चाधिकारियों की जानकारी में लाते हुये अन्य प्रवर्तन इकाइयों को गोपनीय रूप से अवगत कराकर संयुक्त कार्यवाही कराया जाना भी उनका दायित्व है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि सचलदल इकाईयाँ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले माल के साथ-साथ उनके अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरने वाले माल की जाँच नियमित एवं योजनाबद्ध रूप से करते हुए करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगायें।

विशेष अनुसंधान शाखा के द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही से भी यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन इकाईयों द्वारा कोई विशिष्ट कार्ययोजना बना कर कार्यवाही नहीं की जाती है। विशेष अनुसंधान शाखा से यह अपेक्षित है कि वह अपने क्षेत्र में हो रहे करापवंचन के तरीकों का अध्ययन करें, और कार्ययोजना तैयार करें तथा राजस्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ट्रेड से सम्बन्धित बड़ी इकाईयों के सम्बन्ध में निरन्तर अभिसूचना एकत्रित करके उसका मिलान उनके द्वारा कर-निर्धारण अधिकारियों के यहाँ घोषित आकड़ों से करते रहें। प्रत्येक विशेष अनुसंधान शाखा का यह दायित्व है कि उनके अधिकार क्षेत्र में करापवंचन न होने पाये तथा करापवंचन का कोई भी प्रयास जल्दी से जल्दी विभाग की पकड़ में आ जाये, इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। विशेष अनुसंधान शाखा का यह भी दायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत व्यापारियों / निर्माता व्यापारियों के द्वारा भेजे जाने वाले माल एवं प्राप्त किये जाने वाले माल की योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार जाँच करते रहें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित व्यापारी / निर्माता करापवंचन में लिप्त तो नहीं है। विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों को बड़े करापवंचकों के विरुद्ध नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही हेतु स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग लेकर प्रभावी कार्यवाही समय रहते करना अत्यन्त आवश्यक है। विशेष अनुसंधान शाखा का यह भी दायित्व है कि उन्हें जब भी करापवंचन की किसी मोडेल आपरेन्डी की जानकारी हो तो वह तत्काल उसे अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश की अन्य सम्बन्धित इकाईयों को भी अवगत कराये ताकि प्रभावी रूप से सभी करापवंचक व्यापारियों के विरुद्ध एक साथ कार्यवाही पर विचार किया जा सके।

जांच चौकियों पर तैनात अधिकारियों द्वारा प्रपत्रों एवं वाहनों की जांच गहनता से न किये जाने के कारण ऐसे प्रकरण प्रकाश में आते रहे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि विभिन्न " मोडेल आपरेन्डी " अपनाते हुए लम्बे समय तक करापवंचन किया जाता रहता है तथा विभाग को इसे रोकने में बहुत विलम्ब से सफलता मिल पाती है एवं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इससे यह संकेत मिलता है कि पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा जांच चौकियों पर पास किये जा रहे प्रपत्रों से स्पष्ट होने वाले ट्रेड्स की नियमित समीक्षा करके यथोचित कार्यवाही नहीं की जाती है। आवश्यक यह है कि सभी अधिकारी इस सम्बन्ध में सजग रहते हुए गहन जांच

करें तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को भी तत्काल अवगत कराये। यदि मुख्यालय स्तर से किसी कार्यवाही की अपेक्षा हो तो तत्काल मुख्यालय को अवगत कराना आवश्यक है।

प्रवर्तन इकाइयों द्वारा योजना बनाकर ठोस एवं सार्थक कार्यवाही न किया / कराया जाना खेदजनक है। करापवंचन रोकने की दिशा में ठोस / सार्थक कार्यवाही किये जाने का दायित्व प्रवर्तन कार्य में लगे सभी अधिकारियों का है किन्तु किसप्रकार, किस तरीके से कहाँ एवं कैसे करापवंचन हो रहा है एवं उसे किस कारगर ढंग से रोका जा सकता है / प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है, यह तभी संभव है जब इस संबंध में पहले से ही कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार हो। यह कार्य सफलतापूर्वक तभी हो सकता है जब जोनल / संभागीय नियंत्रक /पर्यवेक्षक अधिकारी यथा- जोनल एडिशनल कमिशनर, संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (वि० नु०शा०/प्रवर्तन) अपनी देखरेख में प्रभावी कार्ययोजना तैयार कराये एवं उसपर ठोस एवं सार्थक कार्यवाही कराते हुये परिणाममूलक कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

अतः समस्त जोनल एडिशनल कमिशनर ज्वाइन्ट कमिशनर (वि० नु०शा०/प्रवर्तन) / डिप्टी कमिशनर (प्रवर्तन / वि० नु०शा०) से अपेक्षित है कि वे प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों को उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्य योजना बनाकर प्रभावी ढंग से करापवंचन रोकने की दिशा में ठोस एवं सार्थक कार्यवाही करने / कराने के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराये एवं अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा करें एवं जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही मुख्यालय स्तर से अपेक्षित हो, उनके संबंध में केवल जोनल एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर अपने स्तर से अपनी स्पष्ट तथ्यात्मक आख्या / संस्तुति सहित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें।

संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) से अपेक्षित है कि प्रवर्तन इकाई अथवा वि० नु०शा० इकाई द्वारा प्रेषित किए गये बिल / गोपनीय प्रतिवेदन पर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी से समयबद्ध कार्यवाही (अर्थदण्ड/ कर निर्धारण) कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए।

(सुनील कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन उ०प्र० शासन, लखनऊ।

2. अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश , 5 , मीराबाई मार्ग , लखनऊ ।
3. समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
5. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / अपील /उच्च न्याय कार्य /सर्वोच्च न्याय कार्य)वाणिज्य कर, 30 प्र० ।
6. समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण / राज्यप्रतिनिधि //जॉच चौकी) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त वाणिज्य कर अधिकारी , वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
10. चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर ,
मुख्यालय , लखनऊ ।